

डालमिया सीमेंट लिमिटेड, राजस्थान

बनाम

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली

अप्रैल 16, 1999

[एम. श्रीनिवासन और उमेश सी. बनर्जी, न्यायाधिपति]

आय कर अधिनियम, 1961

धारा 28 -आयकर -निर्धारिती-दो सीमेंट कारखानों को बेचने और स्थानांतरित करने के लिए दिनांक 24.7.1962 का समझौता -दिनांक 2.11.1962 का पूरक समझौता खंड 3 में यह निर्धारित किया गया है कि उक्त कारखानों से होने वाले लाभ और हानि हस्तांतरणकर्ता के खाते में जाने के लिए -दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा परिसंपत्तियों का वास्तविक हस्तांतरण बिक्री के लिए समझौते के बाद लेकिन वास्तविक हस्तांतरण से पहले दोनों कारखानों से होने वाले लाभ -कर का भुगतान करने की देयता -निर्धारण-कहा गया, शीर्षक को ओवरराइड करके आय का विचलन किया गया था वास्तविक उपार्जन से पहले ही अंतरिती के पक्ष में - बिक्री समझौते के बाद निर्धारिती लाभ को बनाए रखने में सक्षम नहीं है - इस प्रकार, निर्धारिती के हाथों में लाभ कर योग्य नहीं है।

धारा 60 और 63-की प्रयोज्यता - आयकर-व्यवसाय का लाभ-संग्रह-धारित, लाभ दिन-प्रतिदिन नहीं बल्कि लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित होता है। शब्द और वाक्यांश - "स्थानांतरण"----- एस.63 आय का कर अधिनियम, 1961 के संदर्भ में इसका अर्थ और दायरा।

अपीलार्थी-निर्धारिती, दिनांक 24.7.1962 के एक समझौते द्वारा अपने दो सीमेंट कारखानों को एक 'एम' को बेचने और स्थानांतरित करने पर सहमत हुए। इसके बाद, पूरक समझौते दिनांक 2.11.1962 खंड 3 में निर्धारित किए गए पक्षों में समझौता किया गया था कि 30.9.1962 के बाद दो कारखानों से होने वाला लाभ और हानि हस्तांतरणकर्ता के खाते में जाएगा। समझौते को समय-समय पर बढ़ाया जाता था और अंततः, 30.9.1964 पर, एक बिक्री विलेख में पक्षों ने प्रवेश किया। निर्धारिती ने मूल्यांकन के लिए अपनी आय-कर विवरणी अवधि 1.10.1962 से 30.9.1963 और 1.10.1963 से 30.9.1964 उक्त दो सीमेंट कारखानों से होने वाला लाभ को छोड़कर दाखिल की। आय-कर अधिकारी ने उक्त विवरणी को अस्वीकार करते हुए एक निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें उक्त दो सीमेंट कारखानों से होने वाला लाभ शामिल किया गया था। निर्धारिती ने अपीलीय सहायक आयुक्त और न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त मूल्यांकन आदेश को असफल रूप से चुनौती दी। संदर्भ पर, उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी-निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय की लाभ के स्वामित्व या स्वामित्व के बजाय कारखानों के भौतिक नियंत्रण के तथ्य पर अपनी निर्भरता के कारण स्पष्ट त्रुटि थी, जो पूरी तरह से खरीदार और विक्रेता के बीच समझौते का विषय था; उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के कारण लाभ के संचय से संबंधित कानून को गलत पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है कि पूरक समझौते में स्वयं यह दर्ज किया गया है कि लाभ हस्तांतरणकर्ता 'एम' के खातों में होना चाहिए, अधिनियम की धारा 60 की प्रयोज्यता के बारे में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष भी पूरी तरह से गलत था एस 60 और एस 63 आय-कर अधिनियम, 1961 की भाषा को ध्यान में रखते हुए अनुचित है।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 . अपीलार्थी-निर्धारिती पर लाभ के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है आंकलन अवधि 1.10.1962 से 30.9.1963 और 1.10.1963 से 30.9.1964 के लिए पाकिस्तान में स्थित दो सीमेंट कारखानों से उत्पन्न होता है क्योंकि हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में स्वामित्व को ओवरराइड करके आय का विचलन किया गया था। [ 749 - ए-बी; 738-डी-जी]

1.2 . कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि आय के विचलन की स्थिति में स्वामित्व को ओवरराइड करके, निर्धारिती के हाथ में आय

का मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता है और न ही उत्पन्न हो सकता है। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि किसी घटना के आधार पर अधिभावी स्वामित्व का मुद्दा, जो अभी घटित नहीं हुआ है, विचाराधीन मामले के तथ्यों में उपलब्ध नहीं होने के कारण, मूल्यांकन की तिथि के बाद से, कानून की सही सराहना नहीं हो सकती है। घटना पहले ही हो चुकी है और एक सर्वोपरि शीर्षक वास्तव में कानून के संचालन द्वारा बनाया गया है और इससे कोई बच नहीं सकता है। [746-ए-सी] ए]

सी. आई. टी बनाम शीतलदास तीरथदास, (1961) 41 आई. टी. आर. 367 और त्रावणकोर शुगर और केमिकल, (1973) 88 आई. टी. आर. 1, पर निर्भर।

आय कर आयुक्त बनाम झान्जी टी एसोसिएशन, (1989) 178 आई. टी. आर. 296 और आयकर आयुक्त बनाम. एम. डी. कनोरिया, [1982] 137 आई. टी. आर. 137, अनुमोदित।

1.3 . तत्काल मामले में, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि संबंधित तिथि 30.9.1962 होना चाहिए न कि बिक्री का पूरा होना। जिस समझौते के खंड 3 का, उच्च न्यायालय ने एक विशेष संदर्भ दिया और व्याख्या की कि आकस्मिक घटना के कारण जो लाभ के संचय के बाद होगी, लाभ को निर्धारिती के हाथों में माना जा सकता है, वह शुद्धता की

कसौटी का सामना नहीं करता है। 'बिक्री समझौते' के बाद निर्धारिती को अपने हाथ में लाभ बनाए रखने में सक्षम बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। किसी भी स्थिति में व्यवसाय का लाभ दिन-प्रतिदिन नहीं बल्कि लेखांकन वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। लाभ का निर्धारण 30.9.1964 पर किया गया था। जब संपत्ति को वर्ष 1965-66 के लिए इस तरह से हस्तांतरित किया गया था, तो निर्धारिती को होने वाले लाभ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तथ्य की बात यह है कि लाभ क्रेता को दिनांक 24.7.1962 के समझौते के अनुसार और 2.11.1962 के पूरक समझौते के साथ पढ़े गए और प्रश्न में कारखाने के वास्तविक हस्तांतरण की सी तारीख के अनुसार दिया जाता है, जो वास्तव में, है 30.9.1964 को हुई घटना से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तथ्य यह है कि आय को संचय से पहले ही एक अधिभावी शीर्षक द्वारा विचलित कर दिया जाता है। [ 743 - एफ-एच; 744-ए-बी]

2. आयकर अधिनियम की धारा 60 केवल एक मामले में लागू होती है जहाँ आय अंतरिती को उपार्जित होती है लेकिन आय अर्जित करने वाली संपत्ति या आय का स्रोत हस्तांतरणकर्ता के पास रहता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि हस्तांतरणकर्ता को उपार्जित आय इस निष्कर्ष से विरोधाभासी है कि विचाराधीन मामले के तथ्यों में धारा 60 का उचित अनुप्रयोग है। संयोग से, एस. 63 में एस. एस. 60 से 62 तक के

उद्देश्यों के लिए "स्थानांतरण" की एक विशेष परिभाषा है और अन्य बातों के साथ-साथ एक "समझौता" शामिल है और इस मामले में 24 जुलाई, 1962 के हस्तांतरण समझौते का अस्तित्व ही अधिनियम की धारा 60 के अनुप्रयोग को पूरी तरह से खारिज करता है और पूरी तरह से बाहर करता है। इस प्रकार, धारा 60 की प्रयोज्यता के संबंध में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को कानून के ज्ञात सिद्धांतों के अनुसार अन्यथा नहीं माना जा सकता है, जिसमें उसमें उपयोग की गई भाषा को उचित रूप से ध्यान में रखा गया है और उच्च न्यायालय ने वास्तव में प्रावधान का गलत अर्थ निकाला है और इस प्रकार एक त्रुटि में पड़ गया है। [447 - ई-जी; 748-सी-डी]

3. कारखानों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ का मूल्यांकन और पूंजीगत लाभ की आय के संचय पर निष्कर्ष के बीच स्पष्ट विसंगति प्रतीत होती है चूंकि पूंजीगत लाभ की गणना लाभ की सकल राशि को बिक्री मूल्य के रूप में विचार करने से प्रभावित होती है। इस प्रकार आयकर अधिकारी ने निहितार्थ से यह स्वीकार कर लिया गया कि लाभ अंतरिती का है, न कि उसका हस्तांतरणकर्ता का -अन्यथा, बिक्री मूल्य के रूप में भुगतान की गई शुद्ध राशि ही ली जानी चाहिए थी। उच्च न्यायालय का निर्णय न केवल स्पष्ट असंगति से ग्रस्त है बल्कि स्थिति की समग्रता स्वाभाविक रूप से विरोधभासी है। [ 748 - जी-एच; 749-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4632-33/1992

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 9.10.91 के निर्णय और आदेश से जो कि एस सी.ए.सं. 1 और 2/1991 में पारित किया गया।

जोसेफ वेल्लापल्ली, सुश्री सुष्मिता बनर्जी और तरुण गुलाटी अपीलार्थी के लिए मेसर्स खेतान एंड कंपनी के लिए।

प्रतिवादी की ओर से डॉ. वी. गौरी शंकर, एस. राजप्पा और बी. के. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय दिया गया:

बनर्जी, न्यायाधिपति

विशेष अवकाश के अनुदान द्वारा इन अपीलों को निर्देशित किया जाता है आय -कर संदर्भ संख्या.87 और 88/1974 उच्च न्यायालय के एक सामान्य आदेश के खिलाफ निर्धारण वर्ष 1964-65 और 1965-66 के संबंध में आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली शाखा द्वारा निर्देश के आदेश के संदर्भ में।

न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित दो प्रश्नों को उच्च न्यायालय को भेजा है उपर्युक्त मूल्यांकन वर्षों 1964-65 और 1965-66 के लिए।

मूल्यांकन वर्ष 1964-65 के लिए प्रश्न निम्नानुसार है:

"तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करना सही था कि दो पाकिस्तान स्थित फैक्ट्रियों से आवेदक कंपनी का उत्पन्न लाभ वर्ष 1.10.1962 से 30.9.1963 के लिए कर योग्य था?"

और मूल्यांकन वर्ष 1965-66 के लिए प्रश्न था:

"चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करना सही था कि दो पाकिस्तान स्थित सीमेंट फैक्ट्रियों से आवेदक कंपनी का उत्पन्न लाभ वर्ष 1.10.1963 से 30.9.1964 के लिए कर योग्य था?"

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दोनों मूल्यांकन वर्षों के प्रश्नों का सकारात्मक रूप से उत्तर दिया और इसलिए ये अपीलें हैं।

इस मोड़ पर, तथ्यों की प्रासंगिकता पर संक्षेप में ध्यान देना सुविधाजनक होगा। पाकिस्तान में स्थित दो सीमेंट कारखानों की मालिक निर्धारिती डालमिया सीमेंट लिमिटेड ने 24 जुलाई, 1962 को एक लिखित समझौते के माध्यम से मानेकजी को अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों को बेचने और हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। पाकिस्तान ने दो सीमेंट कारखानों में प्रतिनिधित्व किया।



तथ्य आगे बताते हैं कि समझौते के बाद, पक्षकार 2 नवंबर, 1962 को एक पूरक समझौता किया। हम वर्तमान में दोनों समझौतों का उल्लेख करेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले, निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाए कि निर्धारिती ने 30 जून, 1964 को निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिए अपनी आय की वापसी में कुल आय इस प्रकार दर्ज की रु.24,28,675/- लेकिन बाद में 20 नवंबर, 1968 को दाखिल किए गए एक संशोधित रिटर्न पर, दिखाई गई कुल आय घटकर रु. 1,40,852/- हो गई। इसी तरह वर्ष 1965-66 के लिए 30 जून, 1965 को दाखिल की गई विवरणी में कुल आय दर्ज की गई- रु..24,58,314/- लेकिन संशोधित रिटर्न ने रु. 2,45,786/- के नुकसान को दर्शाया। हालांकि मूल प्रतिफल में पाकिस्तान के दो कारखानों के काम करने से होने वाला लाभ शामिल नहीं था, बल्कि केवल दो साल की अवधि के लिए ब्याज आय शामिल थी 1.10.1962 से 30.9.1964 को, जिसे हालांकि उसकी प्राप्ति न होने के आधार पर संशोधित विवरणी में हटा दिया गया था।

आयकर अधिकारी ने हालांकि इस तर्क को खारिज कर दिया कि लाभ दोनों कारखानों में से श्री मानेकजी या उनके नामित व्यक्ति के हैं जो 1.10.1962 से प्रभावी हैं और आयकर अधिकारी के मूल्यांकन में दोनों कंपनियों के लाभ को दोनों वर्षों के लिए निर्धारिती कंपनी की कुल आय में शामिल किया गया है। अपीलीय सहायक आयुक्त की एक अपील पर दोनों

वर्षों के लिए आय-कर अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई। निर्धारिती द्वारा की गई अपील में न्यायाधिकरण का आदेश भी ऐसा ही है जिसमें एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि 30.9.1962 के बाद और 30.9.1964 से पहले उत्पन्न होने वाले लाभ निर्धारिती कंपनी के हाथों में कर योग्य थे। इसके बाद यह मामला उपर्युक्त दो प्रश्नों पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उच्च न्यायालय ने जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसी का सकारात्मक उत्तर दिया।

हालाँकि इस समय 24 जुलाई, 1962 के समझौते पर ध्यान देना सुविधाजनक होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

" ..... और जबकि, कंपनी श्री मानेकजी को बेचने और स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो गई है उक्त व्यवसाय से संबंधित पाकिस्तान में अपनी सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों जिनका पिछले पैराग्राफ में संक्षेप में उल्लेख किया है और इसके बाद विचार के लिए विस्तार से बताया है और उन नियमों और शर्तों पर जो इसके बाद दिखाई देता है।

..... उक्त बिक्री के लिए प्रतिफल निम्न तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा और इस तरह से निर्धारित कुल राशि (कटौती करके कम 20,00,000 बीस लाख रुपये) को इसके बाद से "कीमत" कहा जाता है।

(ए) यहां उल्लेखित अनुसूची में पूरी तरह से वर्णित सभी अचल संपत्तियों के लिए श्री मानेकजी द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत 30 सितंबर, 1962 को कंपनी के खातों की किताबों में उनका मूल्य होगा जिसे इसके बाद "कहा जाएगा" मूल्यांकन दिवस" मूल्यांकन दिवस और लेन-देन पूरा होने की तारीख के बीच खरीदी, बेची, क्षतिग्रस्त या नष्ट की गई अचल संपत्तियों के लिए बही कीमतों पर समायोजन के अधीन है, जिसे इसके बाद "समापन दिवस" कहा जाएगा (सामान्य) टूट-फूट को छोड़कर);

(बी) श्री मानेकजी को हस्तांतरित की जाने वाली फायरब्रिक्स, ग्राइंडिंग मीडिया, गनी बैग, स्पेयर पार्ट्स, जनरल स्टोर, कोयला और विविध वस्तुओं सहित सभी दुकानों के लिए श्री मानेकजी द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत खाते की किताबों में उनका मूल्य होगा मूल्यांकन दिवस पर कंपनी का, मूल्यांकन दिवस और समापन दिवस के बीच खरीदी गई, निर्मित, प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त, बेची गई या नष्ट की गई उपरोक्त वस्तुओं के लिए बही कीमतों पर समायोजन के अधीन;

(सी) पारगमन में सभी वस्तुओं, कच्चे माल, प्रक्रिया में, क्लिंकर (आधे बने सीमेंट), निर्मित सीमेंट, डंडोट फैक्ट्री द्वारा निर्मित फायरब्रिक्स के लिए श्री मानेकजी द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत खाते की किताबों में उनका मूल्य होगा मूल्यांकन दिवस पर कंपनी, मूल्यांकन दिवस और समापन दिवस के बीच खरीदी गई, निर्मित, प्रक्रिया में, क्षतिग्रस्त, बेची

गई या नष्ट की गई उपरोक्त वस्तुओं के लिए बही कीमतों पर समायोजन के अधीन होगी;

(डी) नकद सममूल्य पर हस्तांतरित किया जाएगा।

"18..... लेन-देन का पूरा होना अनुमोदन के अधीन है भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारी एजेंसियों को इस समझौते के क्रियान्वन के लिए कानून द्वारा आवश्यक और अपेक्षित स्वीकृतियों की सीमा तक, और श्री मानेकजी पाकिस्तान सरकार से उक्त सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे। कंपनी एतद्द्वारा भारत सरकार से उक्त सभी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने का वचन देती है।

19. इस समझौते की विषय वस्तु का हस्तांतरण होगा 31 दिसंबर, 1962 को या उससे पहले पूरा किया जाएगा और जब तक कि अन्यथा न हो लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत होने पर, यह समझौता उसी दिन समाप्त हो जाएगा।

20. इस समझौते और/या इसकी विषय -वस्तु को श्री मानेकजी द्वारा गठित और नियंत्रित किसी भी निगमित को हस्तांतरित किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो और कंपनी हस्तांतरण को प्रभावित करने

के लिए बाध्य होगी जैसे कि बाध्य होगी जैसे कि ऐसा निगमित निकाय इसमें एक पक्ष था।"

इस समय निम्नलिखित पूरक समझौते की कुछ शर्तों पर ध्यान देना भी सुविधाजनक होगा :

"इसलिए अब दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति है कि: उक्त समझौते के खंड 2 को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

उक्त बिक्री का विचार निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा और उसके द्वारा सुनिश्चित की गई कुल राशि (20,00,000 रुपये की कटौती को छोड़कर) को इसके बाद खरीद मूल्य कहा जाएगा।

(ए) श्री मानेकजी द्वारा सभी अचल संपत्तियों के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत 30 सितंबर, 1962 को कंपनी की लेखा बहियों में उनका मूल्य होगा जिसे इसके बाद "मूल्यांकन दिवस" कहा जाएगा।

X X X

(डी) 30 सितंबर 1962 तक पाकिस्तान में कंपनी द्वारा रखी गई सभी नकदी को, सममूल्य पर हस्तांतरित किया जाएगा।

(ई) निवेश और सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्यांकन दिवस पर औसत बाजार मूल्य पर स्थानांतरित किया जाएगा, सिवाय इसके कि कंपनी द्वारा डालमिया सीमेंट (पाकिस्तान) लिमिटेड, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में रखे गए शेयरों को निर्धारित शेयरों के शुद्ध मूल्य पर स्थानांतरित किया जाएगा 30 सितंबर, 1962 को डालमिया सीमेंट (पाकिस्तान) लिमिटेड की बैलेंस शीट के संदर्भ में।

(एफ) श्री मानेकजी द्वारा कंपनी के सभी ऋणों, अग्रिम बकाया और अन्य ऋणों के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत निर्धारण दिवस पर कंपनी की बही में उनका मूल्य होगा।

श्री मानेकजी द्वारा खरीद मूल्य पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की गणना 1 अक्टूबर 1962 से की जाएगी और उक्त समझौते के पैरा 3 (बी) में दिए गए तरीके से भुगतान किया जाएगा।

कंपनी के संचालन के दौरान होने वाला लाभ और हानि 30 सितंबर, 1962 के बाद की अवधि, उक्त समझौते के अनुसार बिक्री लेनदेन के पूरा होने की स्थिति में, श्री मानेकजी के खाते में होगी। हालाँकि, पाकिस्तान में कंपनी के कारखानों और व्यवसाय का संचालन अब तक की तरह पूर्ण और अबाधित नियंत्रण और कंपनी के निर्देशन में रहेगा, और इसमें कहीं गई किसी भी बात को श्री मानेकजी की ओर से किसी भी तरह से हस्तक्षेप की

अनुमति के रूप में नहीं माना जाएगा कारखानों के व्यवसाय और परिचालन का संचालन के साथ जब तक कि उसे श्री मानेकजी को लेन देन पूरा होने पर हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता है।

उक्त समझौते के पैरा 5 के अधिक्रमण में, इस बात पर सहमति है कि 30 सितंबर, 1962 तक की अवधि से संबंधित कंपनी की सभी देनदारियां, जो इसके द्वारा हस्तांतरित संपत्तियों, परिसंपत्तियों और परिसरों से संबंधित हो सकती हैं, कंपनी की एकमात्र जिम्मेदारी होंगी और श्री मानेकजी 1 अक्टूबर 1962 से शुरू होने वाली अवधि के संबंध में ऐसी सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होंगे।"

संयोग से, यह ध्यान दिया जाए कि 24 जुलाई, 1962 का प्रमुख समझौता, हालांकि समय सीमा थी, उसी को पक्षकारों की सहमति से और पूरक समझौते के माध्यम से समय-समय पर बढ़ाया गया था और खरीद के पूरा होने की अवधि 30.9.1964 तक बढ़ा दी गई थी और यह उस तारीख को है जब पक्षों ने निर्धारित डालमिया सीमेंट लिमिटेड द्वारा पाकिस्तान प्रगतिशील सीमेंट उद्योग के पक्ष में अधिकारों के हस्तांतरण लिए एक बिक्री विलेख किया था।

अपील के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेल्लापल्ली ने अपने तर्क में जोर डालकर कहा कि उच्च न्यायालय

स्वामित्व या शीर्षक के बजाय कारखानों के भौतिक नियंत्रण के तथ्य पर निर्भरता के कारण स्पष्ट त्रुटि में था या मुनाफ़े के शीर्षक के लिए जो पूरी तरह से खरीदार और विक्रेता के बीच समझौते का मामला था। ऐसा प्रतीत होता है कि लेन-देन के पूरा होने तक श्री मानेकजी को कारखाने के व्यवसाय और परिचालन के संचालन में तब तक हस्तक्षेप न करने का तथ्य, जब तक कि इसे श्री मानेकजी को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता, उच्च न्यायालय के समक्ष महत्व रखता है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अन्यथा इस तथ्य के कारण लाभ अर्जित करने से संबंधित कानून को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है कि पूरक समझौते में ही यह दर्ज है कि लाभ श्री मानेकजी के खातों में जाना है। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने कहा: "कारोबार के संचालन और कारखानों के संचालन से लाभ एक साथ उत्पन्न होगा। यह सच है कि दिनांकित 20 नवंबर, 1962, पूरक समझौते के खंड 3 के अनुसार मुनाफ़ा श्री मानेकजी के खाते में जाना होगा लेकिन यह केवल एक विशेष तिथि तक बिक्री लेनदेन के पूरा होने की स्थिति में होगा जो लाभ के संचय के बाद होने वाली घटना होगी।

" ..... जब श्री मानेकजी के या उसके नामांकित व्यक्ति हस्तक्षेप के बिना निर्धारित कंपनी द्वारा कारखाने का व्यवसाय और संचालन किया जाना है और बिक्री लेनदेन अभी होना बाकी है जो हो सकता है या नहीं



भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्धारित कंपनी के लाभ के संचय पर कोई रोक नहीं लगेगी। यह सच है कि हाथ में नकदी के साथ-साथ बैंक में, और बैंक के सभी बिल और नोट भी स्थानांतरित हो जाएंगे, लेकिन यह भविष्य की तारीख को होगा जब बिक्री विलेख निष्पादित किया जाएगा। एक ऐसी घटना के संबंध में जो अभी तक नहीं हुई है, अधिभावी शीर्षक अस्तित्व में नहीं आता है, लाभ का संचय केवल तभी रोका जा सकता है जब इससे पहले एक अधिभावी शीर्षक बनाया जाता है।"

हालांकि पहली बार में यह तर्क आकर्षक लगता है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर विचार करने पर उच्च न्यायालय स्पष्ट त्रुटि में है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस वर्ष 1965-66 के लिए जब निर्धारण का आदेश दिया गया था, लाभ का निर्धारण 30 सितंबर, 1964 को किया गया था और संपत्ति स्वयं हस्तांतरित की गई थी, क्योंकि हस्तांतरित परिसंपत्तियों के कारण लाभ के संचय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और न ही उत्पन्न हो सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिक्री लेनदेन के पूरा होने का सामान्य अर्थ होना चाहिए और इस संबंध में प्रासंगिक तथ्यों पर भी उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। बिक्री लेनदेन वास्तव में हुआ है और इस तरह कोई आकस्मिकता नहीं है, जैसा कि पहले के समय में था। यह घटना हुई है और 2 नवंबर, 1962 का पूरक समझौता स्थिति को स्पष्ट और वर्गीकृत करता है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत

हुए कि संबंधित तिथि 30 सितंबर, 1962 होगी और न कि बिक्री पूरी होने पर। जिसके समझौते के खंड 3 में, उच्च न्यायालय ने एक विशेष संदर्भ दिया और व्याख्या की कि आकस्मिक घटना के कारण जो लाभ के संचय के बाद होगी, लाभ को निर्धारिती के हाथों में नहीं माना जा सकता है, यह शुद्धता की कसौटी का सामना नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने इस घटना को कोई महत्व नहीं दिया है जो बिक्री समझौते के कारण पूरी हो गई। 'बिक्री समझौते' के बाद निर्धारिती को अपने हाथ में लाभ बनाए रखने में सक्षम बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, घटना हुई है और घटना के कारण और समझौते के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारिती के हाथों में लाभ का पता लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और न ही हो सकता है। किसी भी स्थिति में व्यवसाय का लाभ दिन-प्रतिदिन नहीं बल्कि लेखांकन वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। लाभ का निर्धारण 30 सितंबर, 1964 को किया गया था जब संपत्ति का हस्तांतरण किया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्धारिती के अर्जित लाभ का सवाल ही नहीं उठता है। वास्तव में लाभ खरीदार को 24 जुलाई, 1962 के समझौते के संदर्भ में और उसके अनुसार दिया जाता है, जिसे 2 नवंबर, 1962 के पूरक समझौते के साथ पढ़ा जाता है और विचाराधीन कारखाने के वास्तविक हस्तांतरण की तारीख जो वास्तव में 30 सितंबर,

1964 को हुई है, स्थिति को नहीं बदलती है। आय वास्तव में उपार्जित होने से पहले ही एक अधिभावी शीर्षक द्वारा विचलित की जाती है।

एक अधिभावी शीर्षक द्वारा आय के विचलन की अवधारणा सी. आई. टी. बनाम शीतलदास तीरथदास [1961] 41 आई. टी. आर. 367 मामले में इस न्यायालय द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है निम्नलिखित तरीके से:

"हमारी राय में, सही परीक्षा यह है कि क्या राशि जिसकी कटौती की मांग की गई है वास्तव में, कभी भी निर्धारिती तक उसकी आय के रूप में नहीं पहुंची। दायित्व, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर मामले में हैं, लेकिन यह प्रकृति है दायित्व की जो निर्णायक तथ्य है। उस राशि के बीच अंतर होता है जिसे एक व्यक्ति अपनी आय से लागू करने के लिए बाध्य है और एक राशि जिसे दायित्व की प्रकृति से नहीं कहा जा सकता है निर्धारिती की आय का हिस्सा बनें। जिसके द्वारा दायित्व आय को निर्धारिती तक पहुँचने से पहले विचलित किया जाता है, यह कटौती योग्य है; लेकिन जहाँ ऐसी आय के निर्धारिती तक पहुँचने के बाद, आय को किसी दायित्व के निर्वहन के लिए लागू किया जाना आवश्यक है, वही परिणाम, कानून, पालन नहीं करता है। यह पहली तरह का भुगतान है जो वास्तव में कर सकता है। क्षमा करें और दूसरा नहीं। यह भुगतान का पहला प्रकार है जो वास्तव में माफ किया जा सकता है और दूसरा नहीं। दूसरा भुगतान केवल अपनी

आय का एक हिस्सा देने का दायित्व है, जो प्राप्त हो चुका है और तब से लागू है। पहला ऐसा मामला है जिसमें आय कभी भी निर्धारिती तक नहीं पहुंचती है, जो यहां तक कि यदि उसे इसे एकत्र करना होता, तो ऐसा करता अपनी आय के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए और उसकी ओर से करता है, जिसे यह देय है।"

त्रावणकोर शुगर एंड केमिकल [1973] 88 आई. टी. आर. 1 के मामले में इस न्यायालय ने उसी परीक्षण को दोहराया और देखा:

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां दायित्व द्वारा आय को विचलित किया जाता है निर्धारिती तक पहुँचने से पहले, यह कटौती योग्य है। लेकिन, ऐसी आय कहाँ लागू करना आवश्यक है किसी दायित्व के निर्वहन के लिए जब निर्धारिती तक पहुँचती है यह केवल आय के अनुप्रयोग का मामला है भुगतान के दायित्व को पूरा करने हेतु और इसलिए कटौती योग्य नहीं है। इस संदर्भ में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पीठ के फैसले का संदर्भ आय-कर आयुक्त बनाम झान्जी टी एसोसिएशन 178 आईटीआर 296 भी उपयुक्त प्रतीत होता है।

एस. सी. सेन, न्यायाधिपति . ( तत्कालीन' हिज लॉर्डशिप 'के रूप में)  
अंतिम नोट किए गए निर्णय में कहा गया:

"यह सच है कि आय-कर देयता किसी समझौते के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है। राजस्व उस व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार है जिसने आय अर्जित की है, लेकिन जहां आय अर्जित होने से पहले ही एक अधिभावी शीर्षक द्वारा विचलित कर दी गई है, तो आयकर अधिकारी इस प्रकार हस्तांतरित आय को हस्तांतरणकर्ता की आय के रूप में आंकने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इस मामले में, न केवल चाय बागानों को हस्तांतरित किया गया था, बल्कि उससे होने वाली आय को भी 1 जनवरी, 1969 से क्रेता को हस्तांतरित कर दिया गया था। उस तारीख से विनिर्माण गतिविधियां क्रेता की ओर से थीं। विनिर्माण गतिविधि से होने वाली आय क्रेता को अर्जित होती थी। विनिर्माण गतिविधि से संबंधित आय क्रेता को अर्जित होती थी। मैं यह देखने में विफल हूं कि ऐसी चाय की बिक्री से प्राप्त हुई आय का मूल्यांकन विक्रेता की आय के रूप में कैसे किया जा सकता है।"

इस संबंध में की गई टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है जी. के. मित्र, न्यायाधिपति द्वारा सी. आई. टी. बनाम भारत की चाय उत्पादक कंपनी लिमिटेड, (1963) 48 आई. टी. आर. 200 (कैल), मामले में जहाँ यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति को धारा 10 के तहत मूल्यांकन से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि उसे दिखाया जाना चाहिए यह वह था जो व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय चलाता था और व्यवसाय के मामले में,

किसी भी व्यक्ति के लिए यह खुला था कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उसका प्रभारी बना सकता था, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह व्यवसाय होता था उस व्यक्ति का था जिसके पास इसका स्वामित्व था और अधिनियम की धारा 10 के तहत व्यवसाय का ऐसा मालिक निर्धारित होगा। उस मामले में यह देखा गया कि (पेज 206 पर):

"यदि ए द्वारा चलाया जाने वाला व्यवसाय बी को हस्तांतरित किया जाता है किसी समय बिंदू पर अकेले बी का आंकलन कर के लिए उस अवधि के संबंध में स्वामित्व के परिवर्तन के बाद से किया जा सकता है। ए और बी सहमत हो सकते हैं कि पूर्ववर्ती तिथि से व्यवसाय का कोई लाभ या हानि स्वामित्व का परिवर्तन के बाद से बी के खाते में होगा। ऐसे मामले में ए को व्यवसाय की आय और लाभ के लिए बी को लेखा देना होगा जो समझौते की अवधि के अंतर्गत आता है और ए ने माना जा सकता है कि सहमत तिथि से बी के एजेंट के रूप में व्यवसाय किया।

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया है आय -कर आयुक्त बनाम एम. डी. कनोरिया, [1982] 137 आईटीआर 137 मामले में।

इस प्रकार कानून को मामलों के एक लंबी श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से निपटाया गया प्रतीत होता है इस हद तक कि उनके स्वामित्व को अधिभावी करके आय का विचलन होने की स्थिति में, निर्धारिती के हाथ में मूल्यांकन की जा रही आय का सवाल पैदा नहीं होता है और न ही हो सकता है।

यहां यह ध्यान दिया जाए कि उच्च न्यायालय स्तर तक की कार्यवाही के किसी भी चरण में निर्धारिती के स्वामित्व को अधिभावी करके विचलन के विवाद के संबंध में कोई विवाद नहीं था। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि किसी घटना के आधार पर अधिभावी स्वामित्व का मुद्दा, जो अभी घटित नहीं हुआ है, विचाराधीन मामले के तथ्यों में उपलब्ध नहीं होने के कारण, हमारे विचार में इसे कानून की सही सराहना नहीं कहा जा सकता है, चूंकि मूल्यांकन की तारीख पर, घटना पहले ही हो चुकी है और एक अधिभावी शीर्षक वास्तव में कानून के संचालन द्वारा बनाया गया है और इससे कोई बच नहीं सकता है और इस तरह हम इसके साथ अपनी सहमति दर्ज करने में असमर्थ हैं।

श्री वेल्लापल्ली ने अगले मामले में तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 60 की प्रयोज्यता के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष भी धारा 60 और धारा 63 की भाषा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अनुचित है।

सुविधा के लिए धारा 60 और 63 यहाँ नीचे दी गई हैं:

"धारा 60. जहां परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं है, वहां आय का स्थानांतरण - किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरण के आधार पर उत्पन्न होने वाली सभी आय, चाहे वह प्रतिसंहरणीय हो या नहीं और चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में हुई हो, जहां कोई हस्तांतरण नहीं होता है जिन परिसंपत्तियों से आय उत्पन्न होती है, उन पर हस्तांतरणकर्ता की आय के रूप में आयकर लगाया जाएगा और उसकी कुल आय में शामिल किया जाएगा।

धारा 63 "हस्तांतरण" और "प्रतिवर्ती हस्तांतरण" परिभाषित-इस धारा की धारा 60,61 और 62 के उद्देश्य के लिए

(ए) किसी हस्तांतरण को रद्द करने योग्य माना जाएगा यदि -

(i) इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय या परिसंपत्तियों के पूरे या किसी भाग का हस्तांतरणकर्ता को, पुनः हस्तांतरण के लिए कोई प्रावधान है, या

(ii) यदि, किसी भी तरह से, हस्तांतरणकर्ता को फिर से सत्ता ग्रहण करने का अधिकार देता है आय या संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ;



(बी) "हस्तांतरण" में कोई करार, ट्रस्ट, नियम, समझौता या व्यवस्था" शामिल है।

उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करते हुए कहा:

"धारा 60 इस बात पर विचार करती है कि आय आयकर के लिए कैसे प्रभार्य होगी जब उन परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है जिनसे आय उत्पन्न हुई है। धारा 63 खंड (बी) किसी भी करार, ट्रस्ट, नियम, अनुबंध या व्यवस्था को शामिल करने के लिए "हस्तांतरण" शब्द को परिभाषित करता है। यदि खंड (बी) में उल्लेखित प्रकृति का कोई दस्तावेज मौजूद है, तो इसे हस्तांतरण माना जाएगा। वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच समझौते हैं। पक्षों के बीच समझौते को हस्तांतरण माना जाएगा लेकिन वास्तव में, परिसंपत्तियों का हस्तांतरण 30 सितंबर, 1964 तक नहीं हुआ था। इसलिए, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से पहले जो भी आय उत्पन्न हुई है, धारा 60 स्पष्ट रूप से विचार करती है कि ऐसी आय जो परिसंपत्तियों के वास्तविक हस्तांतरण से पहले उत्पन्न हुई है हस्तांतरणकर्ता की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभार्य होगा और उसकी कुल आय में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान मामले में, 30 सितंबर, 1964 तक, परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था और 2.11.62 के पूरक समझौते के खंड -3 के

तहत, बिक्री लेनदेन के पूरा होने पर लाभ अंतरिती के खाते में जाना था। भले ही 30 सितंबर, 1964 से पहले लाभ के विचलन के लिए कोई समझौता हो, फिर भी, हमारी राय में, धारा 60 में निहित प्रावधानों के आलोक में, लाभ निर्धारिती कंपनी के हाथों में कर योग्य होगा।"

यह उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष है जिसकी आलोचना अपीलार्थी द्वारा की गई है और हम इस संबंध में इन कारणों से कुछ औचित्य पाते हैं - अधिनियम की धारा 60 में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट भाषा केवल उस मामले में लागू होती है जहां आय अर्जित अंतरिती को होती है लेकिन आय अर्जित करने वाली संपत्ति या आय का स्रोत हस्तांतरणकर्ता के पास रहता है। वास्तव में उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आय हस्तांतरणकर्ता को उपअर्जित इस निष्कर्ष से विरोधाभासी है कि विचाराधीन मामले के तथ्यों में धारा 60 का उचित अनुप्रयोग है।

संयोग से, धारा 63 में "हस्तांतरण" की एक विशेष परिभाषा है धारा 60 से 62 के प्रयोजनों के लिए और अन्य बातों के साथ-साथ एक "समझौता" शामिल है और इस मामले में 24 वीं जुलाई 1962 को हस्तांतरित करने के समझौते का अस्तित्व भी शामिल है जो अधिनियम की धारा 60 के अनुप्रयोग को खारिज करता है और पूरी तरह से बाहर करता है।

हालाँकि न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय से अलग निष्कर्ष दर्ज किया अधिनियम की धारा 60 के लागू होने के मुद्दे के संबंध में। न्यायाधिकरण ने दर्ज किया:

"न ही विभागीय प्रतिनिधि के तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि धारा 60 के तहत 30.9.1962 बाद में उपार्जित लाभ कंपनी के हाथों में प्रभार्य थे। एक बात के लिए इस तर्क की अंतर्निहित धारणा यह होगी कि आय वास्तव में अर्जित की गई थी मानेकजी या उनके नामांकित व्यक्ति जबकि पहले दिए गए कारणों से हम इस धारणा को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, धारा 60 के हमारे पढ़ने के अनुसार यह एक व्यवस्था या निपटान से संबंधित है जिसके अनुसार आय का हस्तांतरण और संपत्ति के स्वामित्व को बनाए रखना दोनों एक योजना के हिस्से बनें।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह दर्ज करना समीचीन समझते हैं कि न्यायाधिकरण का धारा 60 की प्रयोज्यता के संबंध में निष्कर्ष को कानून के ज्ञात सिद्धांतों के अनुसार अन्यथा नहीं माना जा सकता है, इसमें उपयोग की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए और दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने, हम रिकॉर्ड करने के लिए विवश हैं, वास्तव में प्रावधान का गलत अर्थ निकाला है और इस प्रकार एक त्रुटि में पड़ गए हैं।

विशेष रूप से, हालांकि, न्यायाधिकरण ने मामले पर विचार करते हुए अपने आदेश में अभिलिखित "हम इस तथ्य से दर्दनाक रूप से अवगत हैं कि निर्धारिती का मामला कठिन है, कि निर्धारिती को अब तक खरीद मूल्य का कोई हिस्सा नहीं मिला था और पहले अर्जित लाभ के समायोजन के संबंध में स्थिति भी उतनी ही खराब है। लेकिन हमें कानून के प्रावधानों को लागू करना होगा क्योंकि हम उन्हें उन कठिनाइयों से अप्रभावित पाते हैं जिनसे भले ही किसी भी निर्धारिती को गुजरना न पड़े।

जबकि हम निर्धारिती के प्रति न्यायाधिकरण की सहानुभूति की सराहना करते हैं और अभिलिखित करते हैं कि कठिन मामले खराब कानून नहीं बनाते हैं, लेकिन न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने ऊपर देखे गए कानून के साथ पठित मुद्दे में मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के सही परिप्रेक्ष्य की सराहना करने में गलती की है।

मामले के दूसरे पहलू पर भी ध्यान नहीं खोना चाहिए: पूंजीगत लाभ का आंकलन: एक ओर कारखानों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ के आंकलन और दूसरी ओर पूंजी की गणना के बाद से आय के संचय पर निष्कर्ष के बीच स्पष्ट विसंगति प्रतीत होती है चूंकि प्रतिफल की सकल राशि को बिक्री मूल्य के रूप में मानने से लाभ प्रभावित होता था। आय-कर अधिकारी ने इस प्रकार निहितार्थ से लाभ को अंतरिती से संबंधित स्वीकार किया और हस्तांतरणकर्ता से नहीं, अन्यथा अकेले भुगतान की गई

शुद्ध राशि को बिक्री मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए था। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय न केवल स्पष्ट असंगति से ग्रस्त है, बल्कि स्थिति की समग्रता स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी है।

प्रासंगिक तथ्यों में और कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि ऊपर देखा गया है, उठाए गए प्रश्नों पर उच्च न्यायालय की पुष्टि नकार दी गई है और इस प्रकार इसका उत्तर नकारात्मक और निर्धारिती के पक्ष में दिया जाता है।

परिसर में अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश ने न्यायाधिकरण के आदेश के साथ साथ न्यायाधिकरण व आयकर प्राधिकरणों के आदेश को भी दरकिनार कर दिया।

प्रत्यर्थी-कर अधिकारियों को कानून के अनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, इस निर्णय में पहले की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।